[2025] 3 एस.सी.आर. 158: 2025 आईएनएससी 221

वसंत उर्फ गिरीश अकबरसाब सनावले और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 593/2022)

11 फरवरी 2025

जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन, न्यायाधीश

विचारार्थ मुद्दा

हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश की वैधता के संबंध में मुद्दा उठा, जिसमें मृतक पत्नी के पति और सास को बरी करने के फैसले को पलट दिया गया और दोनों को भारतीय दंड संहिता, 1860 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने मृतक को आग लगाकर उसकी हत्या की थी।

दंड संहिता, 1860 - धारा 498ए, 302 और 504 धारा 34 के अंतर्गत - सामान्य इरादा - व्यक्तिगत दायित्व - अपीलकर्ता - मृतक पत्नी के पति और सास पर उसे आग लगाकर हत्या करने का आरोप - मृत्यु पूर्व बयान - निचली अदालत द्वारा धारा 498ए, 302 और 504 धारा 34 और 1961 अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से बरी - हालांकि, उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और दोनों को अपराधों का दोषी ठहराया - शुद्धता:

निर्णय: यद्यपि धारा 34 संयुक्त आपराधिक कृत्य और साझा इरादे से संबंधित है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह इन दोनों मामलों में अपराधी के व्यक्तिगत योगदान के तत्व को पूरी तरह से अनदेखा या समाप्त कर देती है। धारा 34 की पूर्व शर्त यह है कि अपराधी ने इन दोनों मामलों में अपराध में भाग लिया हो। उसने कुछ न कुछ किया हो, चाहे वह कितना भी

मामूली क्यों न हो, या किसी न किसी तरह से आचरण किया हो, चाहे वह कितना भी अस्पष्ट क्यों न हो, जिससे यह संकेत मिलता हो कि वह अपराध में भागीदार और दोषी सहयोगी था। उसे व्यक्तिगत रूप से उस इरादे का भी भागीदार होना चाहिए जिसे वह दूसरों के साथ साझा करता हो। उसे 'आपराधिक कृत्य' और 'साझा इरादे' दोनों में भागीदार होना चाहिए, जो धारा 34 के दोहरे पहलू हैं। धारा 34 की सहायता से भी पति-अपीलकर्ता को कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है- अभियुक्त के लिए यह तर्क देना कठिन है कि आरोप पत्र में धारा 34 का उल्लेख होने के कारण, उसे गुमराह किया गया या उसके बचाव में पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसे यह मान लेने के लिए प्रेरित किया गया कि इसके परिणामस्वरूप उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर विचार पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। - साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत पति को भी कथित अपराध में फंसाने के लिए, अभियोजन पक्ष को पूर्व शर्त के रूप में ऐसे मूलभूत तथ्य प्रस्तुत करने होंगे जो प्रथम दृष्टया कथित अपराध में उसकी संलिप्तता या भागीदारी को दर्शाते हों। - घटना के बाद उसका अचानक गायब हो जाना सामान्य इरादे का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। मृतक द्वारा डॉक्टर के समक्ष दिए गए मृत्युपूर्व मौखिक बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मृत्युपूर्व बयान और डॉक्टर तथा तहसीलदार के मौखिक साक्ष्य में केवल सास का ही उल्लेख है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने सास (अपीलकर्ता संख्या 2) को कथित अपराध का दोषी ठहराया, लेकिन पति (अपीलकर्ता संख्या 1) को धारा 34 की सहायता से हत्या का दोषी ठहराने में गलती की। अपीलकर्ता संख्या 2 की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। अपीलकर्ता संख्या 1 को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 106 - दहेज निषेध अधिनियम, 1961 - धारा 3, 4। [पैरा 37, 39, 41, 58, 63, 87-89, 91-93]

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 34 और 149 - सामान्य इरादा बनाम सामान्य उद्देश्य - धारा 34 और 149 के बीच अंतर - समझाया गया। [पैरा 41-50] दंड संहिता, 1860 - धारा 34 - सामान्य इरादा - आपराधिक कृत्य - अर्थ - समझाया गया। [52-76]

उद्धृत केस कानून

ओम प्रकाश बनाम राज्य, 1956 सीआरएलजे 452; बरेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर, एआईआर 1925 पीसी 1; एम्परर बनाम बरेन्द्र कुमार घोष, एआईआर 1924 कैल 257 (एफबी); श्रीकांतैया रामय्या मुनिपल्ली बनाम बॉम्बे राज्य (एस) [1955] 1 एससीआर: 1177 एआईआर 1955 एससी 287; बशीर बनाम राज्य, एआईआर 1953 सभी 668; फ़ैयाज़ खान बनाम रेक्स, एआईआर 1949 सभी 180; आयडूस बनाम एम्परर, एआईआर 1923 मैड 187; अब्दुल कादर बनाम सम्राट, एआईआर 1946 कैल 452; सुरेश सखाराम नांगारे बनाम महाराष्ट्र राज्य [2012] 7 एससीआर 1186: 2012 (9) निर्णय आज 116 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; साक्ष्य अधिनियम 1872।

मुख्य शब्दों की सूची

दहेज; पत्नी को आग लगाना; बरी होना; मृत्युकालीन बयान; सामान्य इरादा; प्रथम श्रेणी का मुख्य अपराधी; द्वितीय श्रेणी का मुख्य अपराधी; घटना के समय सहायक; घटना के बाद सहायक; घटना से पहले सहायक; घटनास्थल पर उपस्थिति; सामान्य योजना; पूर्व-नियोजित अंत; लगातार कार्य; एक साथ किए गए कार्य; विशेष ज्ञान; व्यक्तिगत अपराधी का इरादा; आपराधिक मनःस्थिति; पूरी सभा का सामान्य उद्देश्य; उकसाना; दर्शक के रूप में घटनास्थल पर उपस्थिति; आपराधिक कृत्य; मृत्युकालीन बयान देने के लिए मन की सही स्थिति; मौखिक मृत्युकालीन बयान; मौखिक साक्ष्य; सभी का सामान्य इरादा; व्यक्तिगत अपराधी; गैरकानूनी सभा।

से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 593/2022

कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ स्थित सर्किट बेंच के दिनांक 06.10.2020 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध, आपराधिक अपील संख्या 100168/2016

पार्टियों के लिए उपस्थिति

एच. चन्द्रशेखर, सलाहकार। अपीलकर्ताओं के लिए.

आविष्कार सिंघवी, ए.ए.जी., वी.एन. रघुपति, विवेक कुमार सिंह, नावेद अहमद, सुश्री साक्षी रमन, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>आदेश</u>

1. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ बेंच द्वारा आपराधिक अपील संख्या 100168/2016 दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेलगावी द्वारा एस.सी. संख्या 151/2013 में

पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 98ए, 302 और 504 के साथ धारा 34 तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया था।

2. अभियोजन पक्ष का कहना है कि मृतक गीता का विवाह अपीलकर्ता संख्या 1, यानी वसंत उर्फ गिरीश अकबरसाब सनवाले से घटना की तारीख से 8 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके तीन बच्चे थे। आरोप है कि विवाह के एक वर्ष बाद पति और उसके परिवार के सदस्यों ने मृतक को परेशान करना शुरू कर दिया। मृतक को दहेज और घरेलू कामों को लेकर परेशान किया जा रहा था।

3. घटना वाले दिन रात लगभग 8 बजे, जब मृतक अपने ससुराल में थी, उसकी सास, यानी अपीलकर्ता संख्या 2 ने कथित तौर पर उसके शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। मृतक बुरी तरह जल गई।

4. आसपास रहने वाले पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। एक सप्ताह बाद जलने से लगी चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण हमेशा की तरह सेप्टीसीमिया था।

5. मृतक की माता तिप्पाव्वा चंद्रू पाटिल ने 03-01-2013 को एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसे मुदलागी पुलिस स्टेशन, मुदलागी सर्कल, जिला बेलगावी, कर्नाटक में अपराध संख्या 2/2013 के रूप में पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट इस प्रकार है:-

> "यहाँ उल्लिखित आरोपी, शिकायतकर्ता की पुत्री गीता के पति, सास और ससुर हैं। उक्त आरोपियों ने विवाह के बाद एक वर्ष तक गीता की सौहार्दपूर्ण देखभाल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने न केवल उसे सुबह जल्दी उठकर घर के काम करने और दूसरों के घर काम करने के लिए मजबूर करके शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि उस पर अपने मायके से 5,000 रुपये लाने का दबाव भी डाला। जब गीता अपने मायके से पैसे नहीं ला पाई, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की मंशा से उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी और उसे जान से मारने का प्रयास किया, इस प्रकार उन्होंने अपराध किया।"

6. एफआईआर दर्ज होने पर जांच शुरू हुई। मृतक का मृत्युपूर्व बयान दर्ज करने के लिए क्षेत्र के तहसीलदार को अस्पताल पहुंचने का अनुरोध किया गया। तहसीलदार घटना के चार घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचे और मृतक का मृत्युपूर्व बयान (प्रदर्श-46) दर्ज किया।
7. विभिन्न गवाहों, विशेषकर मृतक को अस्पताल लाने वाले पड़ोसियों के बयान, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सीआरपीसी") की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। मृतक की मृत्यु के बाद उसके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच के दौरान एकत्र की गई अन्य वस्तुएं, जैसे कपड़े आदि, रासायनिक विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजी गईं।
8. जांच पूरी होने पर पुलिस ने पति और सास के खिलाफ उपर्युक्त अपराध के लिए आरोपपत्र दाखिल किया। चूंकि यह मामला केवल सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के तहत सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।
9. ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 302, 114, 323 और 504 के तहत धारा 34 के साथ क्रमशः तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय किए, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का दावा किया और मुकदमा चलाने की मांग की।

10. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित गवाहों से पूछताछ की:-

"पीडब्ल्यू1 आनंद शंकर सनावाले पीडब्ल्यू2 लक्ष्मण रामप्पा सनावाले।
"पीडब्ल्यू 3 सुशीला दिलीप सनावाले।
"पीडब्ल्यू 4 शब्बीर समशेर सनावाले। "पीडब्ल्यू 5 लता शशिकांत सनावाले।
"पीडब्ल्यू 6 जुलेखा गुलाबसाब सनावाले।
पीडब्लू7 श्रीमती यल्लाव्वा रामू कराले।
"पीडब्ल्यू 8 कृष्ण मुकप्पा शिवल्ली।
"पीडब्ल्यू 9 मलिक चंद्रू पाटिल।
"पीडब्ल्यू 10 प्रकाश शंकर सनावाले।
पीडब्लू11 श्रीमती. तिप्पव्वा चंद्रू पाटिल.

“पीडब्ल्यू 12 हनुमंत भीमा नायक।

पीडब्लू 13 दस्तगीर अब्दुलसाब इनामदार।

पीडब्लू14 डॉ. एडम अल्लासाब नदाफ।

पीडब्लू15 डॉ. गोपाल रामू वागामुडे।

“पीडब्ल्यू 16 शिवानंद बसवंतप्पा धुलाई।

“पीडब्ल्यू 17 सुरेश शंकर मुर्गोड।

“पीडब्ल्यू 18 मारुति यल्लप्पा पदादल्ली।

“पीडब्ल्यू 19 अनिल बलप्पा पदेदार।

“पीडब्ल्यू 20 लक्कप्पा दुर्गाप्पा टड्डी।

“पीडब्ल्यू 21 औद्रम हम्माब्बा बेरी। “पीडब्ल्यू 22 सुरेशबाबू रुद्रप्पा बांदीवद्दार।

“पीडब्ल्यू 23 शरणप्पा एम. ओलेकर।

“पीडब्ल्यू 24 मृथुंजय इरय्या मातापति।

“पीडब्ल्यू 25 डॉ. एन. सुजाता नांजेगौड़ा।

11. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए:-

(i) प्रदर्श पृष्ठ 8 घटना स्थल का महजर

(ii) प्रदर्श पृष्ठ 27 पोस्टमार्टम रिपोर्ट

(iii) प्रदर्श पृष्ठ 30 मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने से पहले डॉक्टर की राय (पीडब्ल्यू 15)

(iv) प्रदर्श पृष्ठ 30 मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने से पहले डॉक्टर की राय (पीडब्ल्यू 25)

(v) प्रदर्श पृष्ठ 46 मृत्यु पूर्व बयान

(vi) प्रदर्श पृष्ठ 54 एफएसएल रिपोर्ट

12. साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया समाप्त होने पर, ट्रायल कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दोनों आरोपियों का आगे का बयान दर्ज किया, जिसमें दोनों आरोपियों ने कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

13. रिकॉर्ड पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने पर, ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और तदनुसार दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।

14. निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले और आदेश से असंतुष्ट होकर राज्य ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और दोनों आरोपियों को कथित अपराध का दोषी पाया। अंततः उच्च न्यायालय ने उन्हें जुर्माने सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

15. उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में, अपीलकर्ता वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

16. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री फाईक-उल-फारूक ने पुरजोर तर्क देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के सुविचारित निर्णय को पलटकर घोर त्रुटि की है। उनके अनुसार, भले ही अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर भिन्न मत संभव हो, उच्च न्यायालय को, एक अपीलीय न्यायालय के रूप में, दोषमुक्ति के निर्णय को पलटने में सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं या अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों के विपरीत हैं।

18. उन्होंने कहा कि जहां तक अपीलकर्ता नंबर 1 यानी पति का संबंध है, उसके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है।

19. उनका कहना है कि मृतक ने न तो डॉक्टर के समक्ष दिए गए अपने मौखिक मृत्यु पूर्व बयान में और न ही तहसीलदार द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान में पति के विरुद्ध कुछ कहा है। इसके विपरीत, विद्वान वकील के अनुसार, मृतक ने तहसीलदार के समक्ष दिए अपने मृत्यु पूर्व बयान में कहा है कि आग बुझाने के लिए पति ने उस पर पानी डाला था।

20. उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उनकी अपील में योग्यता होने के कारण इसे स्वीकार किया जाए और आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया जाए।

21. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री सिंहवी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के फैसले को पलटने और अपीलकर्ताओं को हत्या का दोषी ठहराने में कोई त्रुटि

नहीं हुई है, विधि संबंधी त्रुटि तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर अविश्वास करने का एकमात्र कारण यह था कि अन्य सभी गवाह, विशेष रूप से पड़ोसी, मुकर गए थे और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रहे थे।

22. श्री सिंहवी के अनुसार, मृतक द्वारा गवाह संख्या 15 डॉ. गोपाल रामू वागामुडे के समक्ष दिया गया मौखिक मृत्यु पूर्व बयान और तहसीलदार के समक्ष दिया गया मृत्यु पूर्व बयान (प्रदर्श पी-21) अपीलकर्ता संख्या 2 को कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।

23. अंत में श्री सिंहवी ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि यद्यपि पति प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है या दूसरे शब्दों में, कथित अपराध में प्रत्यक्ष रूप से आरोपित नहीं है, फिर भी यह स्थापित है कि वह घर में मौजूद था और पति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां या कदम उठाए और उसकी ओर से विफलता या चूक उसकी और उसकी मां द्वारा साझा किए गए सामान्य इरादे को इंगित करती है।

24. श्री सिंहवी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पति को अपने निजी ज्ञान में जो कुछ भी था, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में प्रकट करना चाहिए था। किसी भी तर्कसंगत स्पष्टीकरण के अभाव में, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से पति को दोषी ठहराया।

25. उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में, श्री सिंहवी ने प्रार्थना की कि इस अपील में कोई योग्यता न होने के कारण इसे खारिज कर दिया जाए।

<u>विश्लेषण</u>:

26. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों पर मौजूद सामग्रियों का अध्ययन करने के बाद, हमारे विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है?

27. हम सबसे पहले तहसीलदार द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान से शुरू करते हैं।

28. तहसीलदार द्वारा दर्ज किया गया मृत्युपूर्व बयान (प्रदर्श-46) इस प्रकार है: “प्रश्न संख्या 1: क्या आप होश में हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं?

उत्तर: हाँ

प्रश्न संख्या 2: क्या आप बोलने की स्थिति में हैं?

उत्तर: हाँ

प्रश्न संख्या 3: आप अभी कहाँ हैं?

उत्तर: जनरल अस्पताल, गोकाक।

प्रश्न संख्या 4: आपको यहाँ कब और कौन लाया और किस साधन से लाया?

उत्तर: मेरी गली के लोग मुझे कल रात लगभग 8:30 बजे एम्बुलेंस में यहाँ लाए।

प्रश्न संख्या 5: आप पर किसने हमला किया?

उत्तर: मेरी सास ने मुझ पर केरोसिन डाला और मेरी सास जैतुनाबी ने माचिस जलाकर मुझ पर फेंकी और आग लगा दी।

प्रश्न संख्या 6: उनका नाम और पता बताइए?

उत्तर: जैतुनाबी सनावले

प्रश्न संख्या 7: आप उन्हें कैसे पहचानती हैं?

उत्तर: मैं उन्हें पहचानती हूँ।

प्रश्न संख्या 8: आपको चोट कैसे लगी?

उत्तर: मुझे आग से चोटें आई हैं।

प्रश्न संख्या 9: इस्तेमाल किए गए हथियार क्या थे और उनके आकार का वर्णन कीजिए?

उत्तर: केरोसिन और माचिस की तीली।

प्रश्न संख्या 10: आप पर हमला किस स्थान पर हुआ?

उत्तर: मुदलागी स्थित घर में।

प्रश्न संख्या 11: क्या आप अपने शरीर पर लगे घावों को पहचान सकते हैं?

उत्तर: हाँ।

प्रश्न संख्या 12: आपको चोटें कैसे और किस प्रकार लगीं?

उत्तर: केरोसिन डालकर जलाया गया।

प्रश्न संख्या 13: हमले के पीछे क्या उद्देश्य था?

उत्तर: मैं घर में थी और शाम को बच्चों के कारण झगड़ा हुआ। उस समय मेरी सास जैतुनाबी सनावले को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ पर केरोसिन डाल दिया। जब मैं बाथरूम जा रही थी, तो मेरी सास जैतुनाबी ने माचिस की तीली जलाकर मुझ पर फेंक दी। मेरे पति वसंत ने मुझ पर पानी छिड़का लेकिन आग नहीं बुझी और उसी समय गली के निवासी इकट्ठा हुए और मुझे रात लगभग 8.30 बजे एम्बुलेंस में जनरल अस्पताल ले गए।

29. उपरोक्त संदर्भ में अब हम तहसीलदार के मौखिक साक्ष्य पर विचार करेंगे। तहसीलदार गवाह संख्या 21, औद्रम ने अपने मुख्य बयान में इस प्रकार गवाही दी:-

"3-1-2013 को जब मैं गोकाक के तहसीलदार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, तब मुझे मुदलगी पुलिस स्टेशन से (प्रदर्शनी पृष्ठ 42 के अनुसार) एक अनुरोध प्राप्त हुआ, जो मेरे कार्यालय में प्राप्त हुआ।

उसी दिन मैं गोकाक के सरकारी अस्पताल गया और चिकित्सा अधिकारी को (प्रदर्शनी पृष्ठ 32 के अनुसार) एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने गीता के बयान देने की स्थिति के बारे में उनकी राय पूछी। इस पत्र पर मेरे हस्ताक्षर (प्रदर्शनी पृष्ठ 32 (ख)) हैं। उक्त चिकित्सा

अधिकारी ने (प्रदर्शनी पृष्ठ 32) में यह प्रमाणित किया है कि मरीज मौखिक बयान देने में सक्षम थी।

तदनुसार, मैंने गीता का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया है। जब उससे पूछा गया कि उसे अस्पताल कौन, कब और कैसे लाया गया, तो उसने उत्तर दिया कि उसकी गली के निवासी उसे पिछली रात 8:30 बजे एम्बुलेंस से लाए थे।

जब उससे पूछा गया कि उस पर किसने हमला किया, तो उसने जवाब दिया कि उसकी सास ने उस पर बहुत कुछ डाला था। मिट्टी का तेल और चाची, जैतुनाबी ने माचिस की तीली से उसे आग लगा दी।

जब उससे पूछा गया कि क्या वह उसे पहचान सकती है, तो उसने कहा कि वह पहचान सकती है। जब उससे पूछा गया कि उसे चोटें कैसे लगीं, तो उसने जवाब दिया कि उसे जलने की चोटें आई हैं। जब उससे पूछा गया कि अपराध कहाँ हुआ, तो उसने जवाब दिया कि घर पर, मुदलागी में।

चूंकि उनकी हथेलियाँ जल गई थीं, इसलिए मैंने उक्त मृत्यु पूर्व बयान पर उनके बाएं पैर के अंगूठे का निशान लिया।

इसके बाद मैंने उक्त मृत्यु पूर्व बयान पर हस्ताक्षर किए और चिकित्सा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। 4-2-2013 को मुझे एक अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसे प्रदर्श पृष्ठ 44 के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसमें मृतक गीता के मृत्यु पूर्व बयान की सही प्रति जारी करने का अनुरोध किया गया है। 4-2-2013 को मैंने मृत्यु पूर्व बयान की एक सही प्रति और मूल मृत्यु पूर्व बयान वाले एक सीलबंद लिफाफे के साथ सीपीआई को एक पत्र भेजा, जिसे प्रदर्श पृष्ठ 45 के रूप में चिह्नित किया गया है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर प्रदर्श पृष्ठ 45(क) के रूप में हैं।

(खुली अदालत में अतिरिक्त न्यायिक चिकित्सा अधिकारी, गोकाक से प्राप्त एक सीलबंद लिफाफा खोला गया।)

गीता का मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्श पृष्ठ 46 है; मेरे हस्ताक्षर प्रदर्श पृष्ठ 46(क)(ख) हैं; गीता के बाएं पैर के अंगूठे का निशान प्रदर्श पृष्ठ 46(ग) है; चिकित्सा अधिकारी के

हस्ताक्षर प्रदर्श पृष्ठ 46(घ) हैं। मैंने 3-1-2013 को दोपहर 12.15 बजे से 12.25 बजे तक गीता के अंतिम समय के बयान को रिकॉर्ड किया है।

30. दुर्भाग्यवश, तहसीलदार के नाम पर भी कोई उचित जिरह नहीं हुई। जिरह के माध्यम से ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया जिससे यह अविश्वास किया जा सके कि मृतक मृत्यु पूर्व बयान देने की मानसिक स्थिति में नहीं था।

31. अब हम डॉ. गोपाल रामू वागामुडे के साक्ष्य प्रदर्श 17 (पीडब्ल्यू-15) की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉ. गोपाल वाघमुदे ने अपने मुख्य बयान में निम्नलिखित जानकारी दी:-

> "मैं 2011 से गोकाक जनरल अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। 2 जनवरी 2013 को लगभग रात 9:30 बजे, आनंद एस. सनवाले लगभग 28 वर्षीय गीता वसंत सनवाले (निवासी मुदलगी) को जलने की चोटों के इलाज के लिए हमारे अस्पताल लाए थे। गीता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उनकी सास ने उन पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि यह घटना उसी दिन लगभग रात 8:00 बजे हुई थी। जांच करने पर, वह होश में थीं। उन्होंने बताया कि उन्हें प्यास लग रही थी। जांच के दौरान, उनका रक्तचाप 90/70 था और उनकी नाड़ी तेज थी तथा उनके शरीर से केरोसिन की गंध आ रही थी। जांच करने पर, उनके चेहरे और गर्दन पर सामान्य जलने के निशान पाए गए, जबकि उनके दाहिने हाथ पर गहरे जलने के निशान थे।" बायां हाथ, दायां पैर और बायां पैर। पेट और पीठ पर गहरे जलने के घाव पाए गए और ये सभी घाव लाल रंग के दिखाई दे रहे थे। ये सभी चोटें गंभीर प्रकृति की और ताजा थीं। लगभग 90% चोटें जलने से संबंधित थीं। मैंने उक्त मरीज का अस्पताल में भर्ती होकर इलाज किया है। मैंने 3 जनवरी 2013 को भी उनका इलाज किया था। मेरे अलावा, जनरल सर्जन ने भी इस मरीज का इलाज किया है। 3 जनवरी 2013 को, मुदलागी पुलिस स्टेशन के सहायक सूचना अधिकारी ने एक अनुरोध पत्र दिया था जिसमें यह पूछा गया था कि क्या मरीज बयान देने की स्थिति में है या नहीं। जो दस्तावेज़ मुझे अभी दिखाया जा रहा है, वह उस अनुरोध पत्र की कार्यालय प्रति है जो मुझे उसी दिन दिया गया था। इसे Ex.P.30 के रूप में चिह्नित किया गया है। Ex.P.30 पर इसे प्राप्त करने के मेरे हस्ताक्षर हैं। Ex.P.30 में, मैंने अपनी राय लिखी है कि मरीज बयान देने की स्थिति में है। इसे Ex.P.30 (a) के

रूप में चिह्नित किया गया है। मैंने चोटों के संबंध में घाव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो दस्तावेज़ मुझे अभी दिखाया जा रहा है, वह वही घाव प्रमाण पत्र है जो मैंने प्रस्तुत किया है। इसे प्रदर्श पृष्ठ 31 के रूप में चिह्नित किया गया है। गवाह के हस्ताक्षर को प्रदर्श पृष्ठ 31 (क) के रूप में चिह्नित किया गया है। जो दस्तावेज़ मुझे अभी दिखाया जा रहा है, वह तहसीलदार द्वारा हमारे अस्पताल की कनिष्ठ विशेषज्ञ एन. सुजाता को दी गई अनुरोध पत्र की कार्यालय प्रति है। उक्त अनुरोध पत्र पर एन. सुजाता के हस्ताक्षर हैं। उक्त दस्तावेज़ को प्रदर्श पृष्ठ 32 के रूप में चिह्नित किया गया है। प्रदर्श पृष्ठ 32 में, कनिष्ठ विशेषज्ञ सुजाता ने राय दी है और यह बताते हुए हस्ताक्षर किए हैं कि रोगी बयान देने की स्थिति में है। इसे प्रदर्श पृष्ठ 32 (क) के रूप में चिह्नित किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर केरोसिन डालता है, तो प्रदर्श पृष्ठ 31 में वर्णित चोटें लगने की संभावना होती है। उपर्युक्त रोगी को आगे के उपचार के लिए हमारे अस्पताल से हुबली स्थित केआईएमएस अस्पताल में भेजा गया था।

32. फिर से, डॉ. वागामुडे से जिरह नहीं की गई। डॉ. से जिरह के माध्यम से ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका जिससे मृतक द्वारा उनके समक्ष दिए गए मृत्यु पूर्व मौखिक बयान पर अविश्वास किया जा सके।

33. हालांकि, हमारे लिए यह ध्यान देने योग्य है कि पति का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मृत्यु पूर्व बयान और डॉक्टर तथा तहसीलदार के मौखिक साक्ष्य में केवल सास का ही जिक्र है।

34. हमने इस बात की पुष्टि करने के लिए साक्ष्यों की भी जांच की कि क्या मृतक मृत्यु पूर्व बयान देने की स्थिति में थी या नहीं। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि वह बोलने में असमर्थ थी या बेहोश थी।

35. श्री सिंहवी द्वारा पूछे गए एक अत्यंत प्रासंगिक प्रश्न के उत्तर में कि उच्च न्यायालय ने पति को कथित अपराध का दोषी ठहराते समय किन बातों को आधार बनाया, उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान विवादित निर्णय के अनुच्छेद 30 की ओर दिलाया। अनुच्छेद 30 में उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:-

30. गीता के बयान से ही, आरोपियों द्वारा उसके साथ की गई क्रूरता निर्विवाद रूप से और बिना किसी संदेह के सिद्ध होती है। मृत्यु का कारण जलने की चोटें हैं और यह सिद्ध हो चुका है कि ये चोटें आरोपी संख्या 1 और 2 द्वारा पहुंचाई गई थीं; उन पर सामान्य इरादे से आरोप लगाया गया है। यदि अभियुक्त नंबर 1 वास्तव में अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, तो वह तब ऐसा कर सकता था जब उसकी पत्नी जानलेवा हालत में थी और उसके शरीर पर 90-95% तक चोटें आई थीं। यह सब उसकी उपस्थिति में और उसकी पत्नी की शत्रुता के बावजूद हुआ। उसने उसे इलाज के लिए ले जाने की भी जहमत नहीं उठाई। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी पत्नी मर जाए। इस संदर्भ में, अपराध जानबूझकर करने या न करने से संबंधित हो सकता है।

36. ऊपर उल्लिखित अनुच्छेद 30 को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालय ने पति-अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय इस तथ्य को आधार बनाया कि उसने अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने की जहमत ही नहीं उठाई, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह जीवित न रहे। अतः, उच्च न्यायालय के अनुसार, पति को अपनी माता के साथ मिलीभगत का दोषी माना जा सकता है। हम उच्च न्यायालय का स्पष्ट तात्पर्य नहीं समझ पाए हैं।

37. चाहे जो भी हो, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आईपीसी की धारा 34 के आधार पर भी पति-अपीलकर्ता को कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।

आईपीसी की धारा 34 इस प्रकार है:-

> “34. अनेक व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किए गए कार्य—जब कोई आपराधिक कृत्य अनेक व्यक्तियों द्वारा, सभी के सामान्य इरादे से किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कृत्य केवल उसी ने किया हो।”

38. यदि धारा 34 आईपीसी की व्याख्या करने वाला कोई ऐसा निर्णय है जिसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है, तो वह ओम प्रकाश बनाम राज्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है, जो 1956 सीआरएलजे 452 में प्रकाशित हुआ था। न्यायमूर्ति एम.एच. बेग (उस समय वे न्यायाधीश थे) ने इस प्रावधान और इसकी प्रयोज्यता को खूबसूरती से समझाया है।

39. किसी इरादे को सर्वमान्य होने के लिए, यह समूह के प्रत्येक सदस्य पर लागू होना चाहिए। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि धारा स्वयं सर्वमान्य इरादे को 'सभी का सर्वमान्य इरादा' बताती है। अतः, धारा 34, व्यक्तिगत अपराधी के इरादे की उपेक्षा नहीं करती है।

40. यह केवल अपराध करने में कुछ और व्यक्तियों को शामिल करती है और यह मानती है कि समूह के प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के मन में भी वही इरादा संयुक्त रूप से विद्यमान था। यह हो सकता है कि इरादे को सर्वमान्य बताया गया हो, लेकिन इसका अर्थ केवल यह है कि प्रत्येक सदस्य ने इसे दूसरों के साथ साझा किया, न कि कुछ सदस्यों ने इसे साझा किया और अन्य ने नहीं।

41. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत अपेक्षित सामान्य इरादा, अपराध के मूल तत्व, दोषी इरादे या 'अपराधी इरादे' के समान होना आवश्यक नहीं है, जिसे इससे अलग माना जाना चाहिए। बाद वाला पहले वाले के साथ मेल खा सकता है या उससे संबंधित हो सकता है।

42. दूसरी ओर, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत स्थिति बिल्कुल अलग है। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत लगाए गए आरोप में सभा के व्यक्तिगत सदस्यों के इरादे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है और केवल पूरी सभा के सामान्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस स्थिति का परिणाम यह है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत अपराध का दोषी हो सकता है, भले ही उसका स्वयं अपराध करने का कोई इरादा न हो या वह इसके होने से अनभिज्ञ भी हो।

43. ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां किसी व्यक्ति को धारा 149 के तहत अपराध का दोषी पाया जा सकता है, भले ही वह अपराध उसके अपने इरादे के बिल्कुल विपरीत किया गया हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में रहने वाले एक विशेष समुदाय के सभी सदस्यों को खत्म करने के उद्देश्य से एक गैरकानूनी सभा का गठन किया जाता है। जब यह सभा अपनी गैरकानूनी गतिविधियों में व्यस्त हो, तो इसके कुछ सदस्य दूसरे समुदाय के किसी सदस्य से मिल सकते हैं और अपने साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसकी हत्या कर सकते हैं।

44. लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे कि X, जो इस गैरकानूनी सभा का सदस्य है, यह जान ले कि Y उसका पुराना मित्र था। X शायद न चाहे कि उसके इस पुराने मित्र की हत्या हो जाए, और उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसकी मंशा के विपरीत, Y की हत्या हो जाए।

45. यदि ऐसा होता है, तो गैरकानूनी सभा का सदस्य एक्स, उसी सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही अपराध उसकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत और उसकी मंशा के विरुद्ध किया गया हो, बशर्ते यह सिद्ध हो जाए कि अपराध के समय एक्स सभा का सदस्य बना रहा और अपराध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभा के सामान्य उद्देश्य के दायरे में आता हो।

46. इसका कारण यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत आपराधिक दायित्व सभा के विभिन्न सदस्यों की मंशा से नहीं, बल्कि पूरी सभा के सामान्य उद्देश्य से निर्धारित होता है। इसका परिणाम यह है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 149 के तहत, संबंधित धारा के साथ मिलाकर, किसी अपराध के लिए आरोप तय किया जाता है और उस व्यक्ति को केवल संबंधित धारा के तहत ही दोषी ठहराया जाता है, तो वह वैध रूप से शिकायत कर सकता है कि आरोप के तहत उसकी अपनी मानसिक स्थिति पर कभी विचार ही नहीं किया गया, जिसके कारण वह इस मामले में आश्चर्यचकित रह गया और इस प्रकार गुमराह और पूर्वाग्रहित हुआ।

47. उपरोक्त चर्चा के प्रयोजन के लिए, मैं यह मान रहा हूँ कि आईपीसी की धारा 149 के तहत लगाया गया आरोप एक सामान्य आरोप है जिसमें अपराध के व्यक्तिगत कृत्य

को परिभाषित या निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, और आरोप में कहा गया है कि अपराध सभा के किसी अनिर्दिष्ट सदस्य का कृत्य है। धारा 34 के तहत स्थिति भिन्न है। यहाँ अपराधी और अपराध के बीच संबंध कहीं अधिक घनिष्ठ और गहरा है।

48. धारा 34 के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत अपराधी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उस आपराधिक कृत्य से जुड़ा होता है जो अपराध का गठन करता है। अर्थात्, वह न केवल उस कृत्य में भागीदार होता है जिसे एक सामान्य कृत्य कहा गया है, बल्कि उस सामान्य इरादे में भी भागीदार होता है, और इसलिए, इन दोनों ही दृष्टियों से उसकी व्यक्तिगत भूमिका गंभीर खतरे में पड़ जाती है, भले ही यह व्यक्तिगत भूमिका एक सामान्य योजना का हिस्सा हो जिसमें अन्य लोग भी उसके साथ शामिल हुए हों और समान या भिन्न भूमिका निभाई हो।

49. दूसरे शब्दों में कहें तो, जहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत शारीरिक कृत्य और मानसिक स्थिति दोनों ही संदर्भ में संपूर्ण सभा पर ज़ोर दिया जाता है, वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत इन दोनों पहलुओं का भार विभाजित हो जाता है और यह व्यक्तिगत सदस्य के साथ-साथ संपूर्ण समूह पर भी पड़ता है।

50. अतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 34, धारा 149 के विपरीत, व्यक्तिगत और सामान्य पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित करती है, यद्यपि व्यक्तिगत पहलू को ध्यान में रखते हुए इसे सामान्य पहलू का अभिन्न अंग मानती है। इस अर्थ में, भारतीय दंड संहिता की धारा 34, धारा 149 की तुलना में कहीं अधिक सीमित है। अतः, यदि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है और उसे केवल मूल अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसके लिए यह दलील देना आसान नहीं होगा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मामले का कोई व्यक्तिगत पहलू भी है।

51. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अपराधी किसी न किसी रूप में आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, जो इसे न केवल भारतीय दंड संहिता

की धारा 149 से, बल्कि आपराधिक षड्यंत्र और उकसाने जैसे अन्य संबद्ध अपराधों से भी अलग करता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने या करवाने का मात्र समझौता भी किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 में परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए उत्तरदायी बना सकता है। यदि उक्त समझौता अपराध करने के लिए किया गया है, तो ऐसा समझौता स्वयं ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है और समझौते के अतिरिक्त किसी प्रत्यक्ष कृत्य की आवश्यकता नहीं होगी।

52. यदि समझौता किसी ऐसे कार्य को करने के लिए किया गया है जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, तो उसके अनुसरण में कोई प्रत्यक्ष कार्य आवश्यक है। ऐसा प्रत्यक्ष कार्य समझौते में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, न कि केवल उस विशेष आरोपी द्वारा, जो कार्य में भाग लिए बिना भी अपराध का दोषी हो सकता है।

53. दूसरी ओर, आईपीसी की धारा 34 के तहत, मात्र समझौता, भले ही वह सामान्य इरादे का पर्याप्त प्रमाण हो, आईपीसी की धारा 34 के तहत दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह अपर्याप्त होगा, जब तक कि उक्त सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कोई आपराधिक कृत्य न किया गया हो और आरोपी ने स्वयं किसी न किसी रूप में उक्त कृत्य को करने में भाग न लिया हो।

54. अपराध स्वयं पूर्ण हो जाएगा, भले ही जिस कार्य के लिए उकसाया गया है वह न किया गया हो; या, भले ही वह कार्य किया गया हो, उकसाने वाले ने स्वयं उसमें भाग न लिया हो।

इस प्रकार, अपराध करने में वास्तविक भागीदारी, जो धारा 34 की पूर्व शर्त है और इसकी मुख्य विशेषता है, इसे उकसाने के अपराध से अलग करती है।

55. आईपीसी की धारा 34, अंग्रेजी कानून के तहत प्रथम श्रेणी के मुख्य अपराधी और द्वितीय श्रेणी के मुख्य अपराधी कहे जाने वाले व्यक्तियों पर लगाए गए दायित्व का संक्षिप्त रूप से वर्णन करती है और दोनों के अंतर्निहित सिद्धांतों को एक ही धारा में

समाहित करके उन्हें अपराध के समय सहायक के रूप में मानती है, जबकि अन्य को अपराध से पहले और अपराध के बाद सहायक माना जाता है।

56. इस संबंध में, राज्य के विद्वान वकील श्री सिंहवी ने तर्क दिया कि जो व्यक्ति अपराध के समय घटनास्थल पर उपस्थित था, वह आईपीसी की धारा 34 के तहत दोषी होगा, भले ही उसने कुछ न किया हो।

57. घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्ति आईपीसी की धारा 34 के तहत दोषी हो भी सकता है और नहीं भी। यदि वह अपराध में भाग लेने के उद्देश्य से घटनास्थल पर उपस्थित है, तो वह निश्चित रूप से अपराध में भागीदार होने के कारण दोषी होगा। दूसरी ओर, यदि वह केवल एक दर्शक के रूप में वहां उपस्थित है, तो वह दोषी नहीं होगा।

58. उदाहरण के लिए, घटना का प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद होता है, साथ ही हमलावर का सहयोगी भी। पहला व्यक्ति दोषी नहीं है क्योंकि वह केवल अपराध होते हुए देखने के लिए उपस्थित था। दूसरी ओर, दूसरा व्यक्ति दोषी है क्योंकि वह अपराध होते हुए देखने के उद्देश्य से उपस्थित था। दूसरे शब्दों में, अपराध को सुगम बनाने या बढ़ावा देने के उद्देश्य से घटनास्थल पर उपस्थित होना स्वयं आपराधिक कृत्य में वास्तविक भागीदारी के समान है।

59. जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने बरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट, एआईआर 1925 पीसी 1 (सी) के मामले में कहा था, “यह याद रखना चाहिए कि अपराधों में, अन्य बातों की तरह, ‘वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं’।” सम्राट बनाम बरेंद्र कुमार घोष मामले में न्यायमूर्ति मूकर्जी द्वारा दिए गए निम्नलिखित अवलोकन, ए आई आर 1924 सी ए एल 257 (एफबी) (डी), इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं:

> “अपराध को अंजाम देने के लिए आवश्यक होने पर सहायता की अपेक्षा और यह विश्वास कि उसका साथी पास में है और सहायता देने के लिए तैयार है, मुख्य अपराधी को प्रोत्साहित और प्रेरित करता है और उसे अपराध करने के लिए उकसाता है। इस प्रकार सहयोगी द्वारा दी गई सहायता और समर्थन से वह अपराध करने में भागीदार बनता है।”

60. अतः, किसी पक्ष को मुख्य अपराधी ठहराने के लिए यह पर्याप्त है कि यह सिद्ध हो जाए कि उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर एक सामान्य योजना के अनुसरण में कार्य किया; कि उसने एक ही पूर्व-निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ काम किया, और वह इस प्रकार स्थित था कि वह अपने साथियों को सामान्य कार्य की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान कर सके" (पृष्ठ 280)

61. इसी प्रकार, इसी मामले में न्यायमूर्ति रिचर्डसन के निर्णय में निम्नलिखित शिक्षाप्रद टिप्पणियाँ हैं:

> इसके अलावा, यह कहना असंभव है कि क्या होता यदि केवल एक व्यक्ति हत्या को अंजाम देने निकला होता। किसी साथी के नैतिक और शारीरिक समर्थन के बिना, उसका संकल्प टूट सकता था और उसकी पिस्तौल उसकी जेब में ही रह जाती या आत्मविश्वास में कमी उसके निशाने में बाधा डाल सकती थी; या फिर, उसका सफलतापूर्वक विरोध किया जा सकता था और उसे भागने पर मजबूर किया जा सकता था" (पृष्ठ 296)।

62. उसी मामले के पृष्ठ 308 स्तंभ (1) पर न्यायमूर्ति घोष ने पोस्टर के आपराधिक कानून से निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंश उद्धृत किया है:

> "कई व्यक्ति एक साथ या छोटे-छोटे समूहों में एक सामान्य उद्देश्य से निकलते हैं, चाहे वह हत्या हो या कोई अन्य जघन्य अपराध, या कोई अन्य उद्देश्य जो स्वयं में गैरकानूनी हो, और प्रत्येक व्यक्ति को सौंपी गई भूमिका निभाता है; कुछ लोग कृत्य को अंजाम देते हैं, अन्य लोग उचित दूरी और स्थानों पर निगरानी रखते हैं ताकि अचानक हमले को रोका जा सके, या आवश्यकता पड़ने पर सीधे तौर पर शामिल लोगों को भागने में सहायता प्रदान की जा सके। यदि कृत्य हो जाता है, तो कानून की दृष्टि में वे सभी उस समय उपस्थित होते हैं; क्योंकि यह उनका साझा उद्देश्य था, प्रत्येक व्यक्ति एक ही क्षण प्रत्येक में एक ही सामान्य लक्ष्य की ओर अपनी भूमिका निभाता है, और व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका पूरे गिरोह को समर्थन, प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान करती है, और उनके साझा उद्यम की सफलता सुनिश्चित करती है। संक्षेप में, एक सामान्य उद्देश्य को आगे

बढ़ाने के लिए अपराध के विभिन्न भागों को अलग-अलग अंजाम देने वाले व्यक्ति समान रूप से दोषी हैं।"

63. इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह कहना सही नहीं है कि मौके पर मौजूद व्यक्ति कुछ नहीं करता।

64. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में 'आपराधिक कृत्य' शब्द का प्रयोग व्यापकतम अर्थ में किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी शब्द, हावभाव, कार्य या आचरण शामिल है, चाहे वह सक्रिय हो या निष्क्रिय, जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता हो।

65. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में 'आपराधिक कृत्य' में उन सभी कृत्यों या चूकों का समूह शामिल है जो एक सामान्य इरादे से जुड़े होते हैं और अपराध कागठन करते हैं। इसमें शामिल कृत्य समान या भिन्न हो सकते हैं।

66. ऐसे कृत्य एक साथ, क्रमिक रूप से या अंतराल पर किए जा सकते हैं। ऐसे कृत्यों को स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति एक ही समय में किसी व्यक्ति को पीट सकते हैं, और यदि उनके कृत्य किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू होगी। यहाँ कृत्य एक साथ किए गए हैं।

67. उदाहरण के लिए, दो जेलर जिनका कर्तव्य बारी-बारी से किसी कैदी की सेवा करना है, उसे भूखा रखकर मृत्युदंड देने की साजिश रच सकते हैं। इस षड्यंत्र के फलस्वरूप, वे उसे भोजन न देने का निर्णय ले सकते हैं। इस मामले में आचरण चूक के रूप में होता है और अभियुक्तों के कृत्य क्रमिक होते हैं, न कि एक साथ। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति किसी दस्तावेज़ को जाली बनाने का षड्यंत्र रच सकते हैं।

68. एक व्यक्ति किसी दस्तावेज़ का एक भाग एक दिन में बना सकता है और दूसरा व्यक्ति एक महीने के अंतराल के बाद शेष भाग बना सकता है। इस स्थिति में, भले ही दोनों व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग किए गए कृत्यों के बीच अंतराल हो, दोनों व्यक्तियों के कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत आएंगे।

69. ऐसा कृत्य मात्र एक इशारे, अभिव्यक्ति या आचरण से भी हो सकता है जो अपराध का संकेत दे या सहयोगी को पीड़ित की पहचान करने में मदद करे। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की हत्या की साजिश रच सकते हैं। एक उसे जानता हो सकता है और दूसरा उसे न जानता हो सकता है।

70. दोनों के बीच यह सहमति हो सकती है कि जो व्यक्ति उसे जानता है वह पीड़ित के पास खड़ा रहेगा और इस प्रकार हत्या का कार्य सौंपे गए व्यक्ति को पीड़ित की पहचान करने में सक्षम बनाएगा।

यदि यह योजना अंजाम दी जाती है, तो दोनों भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत दोषी होंगे, भले ही पीड़ित के पास खड़ा व्यक्ति केवल घटनास्थल पर उपस्थित था और उसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया। लेकिन अगर इस योजना का विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित के पास अपनी उपस्थिति से उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

71. वास्तव में, पीड़ित के पास उसकी उपस्थिति ने ही अपराध को सफलतापूर्वक अंजाम देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इसमें मात्र एक चूक भी शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, मृतक के कमरे की रखवाली के लिए नियुक्त संतरी हत्यारे से कमरे में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो सकता है ताकि वह हत्या को अंजाम दे सके।

72. यदि हत्यारा पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार आता है और संतरी जानबूझकर उसे कमरे में प्रवेश करने से रोकता है, तो उसने ऐसा कार्य किया है जो हत्या को अंजाम देने में उतना ही प्रभावी योगदान देता है जितना कि स्वयं हत्या का कार्य।

73. वास्तव में, उसकी चूक के बिना हत्या संभव ही नहीं होती। विभिन्न कार्य प्रकृति में काफी भिन्न हो सकते हैं। अतः, यदि दो व्यक्ति चोरी करने की साजिश रचते हैं और ऐसी योजना बनाते हैं जिसके अनुसार उनमें से एक दुकानदार को बातचीत के बहाने पास के कमरे में ले जाएगा, जिससे दुकान असुरक्षित हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति को चोरी करने का मौका मिल जाएगा, और योजना के अनुसार उसे अंजाम दिया जाता है, तो धारा 34,

आईपीसी के प्रावधानों के अनुसार दोनों ही समान रूप से चोरी के दोषी होंगे, भले ही उनके संबंधित कृत्य बहुत अलग प्रकार के हों।

74. ऐसे मामले में, भले ही केवल एक व्यक्ति ने ही वास्तविक चोरी की हो और दूसरे ने दुकानदार से दोस्ताना बातचीत करने के अलावा कुछ नहीं किया हो ताकि उसे घटनास्थल से हटाया जा सके, फिर भी दूसरे की भूमिका पहले वाले से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

75. अतः यह स्पष्ट है कि धारा 34 के तहत आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अपराध में सहभागी होना चाहिए तभी उसे इसके अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। उपरोक्त कारण से, मैं अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क का समर्थन करने में असमर्थ हूँ कि घटनास्थल पर मौजूद एक दोषी सहयोगी को अपराध में सहभागी नहीं माना जा सकता।

76. अपराध में सहभागिता का तत्व ही वह मुख्य विशेषता है जो धारा 34, आईपीसी को धारा 149, आईपीसी और अन्य संबंधित धाराओं से अलग करती है। इस पर कई निर्णयों में जोर दिया गया है।

77. श्रीकांतैया रामय्या मुनिपल्ली बनाम बॉम्बे राज्य (एस) एआईआर 1955 एससी 287 (ई) मामले में, आईपीसी की धारा 34 का अर्थ स्पष्ट करते हुए, न्यायमूर्ति बोस ने निम्नलिखित टिप्पणी की:–

> “इस धारा का सार यह है कि अपराध के वास्तविक घटित होने के समय व्यक्ति का शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। उसका वास्तविक कक्ष में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है; उदाहरण के लिए, वह बाहर द्वार पर पहरा दे सकता है ताकि अपने साथियों को किसी भी खतरे के बारे में चेतावनी दे सके, या पास की सड़क पर कार में बैठकर उनकी भागने में सहायता कर सके, लेकिन उसे घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए और अपराध के घटित होने के समय किसी न किसी रूप में अपराध में वास्तव में भाग लेना चाहिए। प्रारंभिक चरण, समझौता, तैयारी, योजना, जो धारा 109 के अंतर्गत आते हैं, और अपराध के घटित होने का चरण, जब योजनाओं को लागू किया जाता है और क्रियान्वित

किया जाता है, के बीच विरोधाभास है। धारा 34 बाद वाले चरण से संबंधित है", (पृष्ठ 293)।

78. उसी फैसले के पृष्ठ 294, स्तंभ (1) में यह टिप्पणी की गई है कि:–

"धारा 34 में 'किया गया' शब्द पर जोर दिया गया है। जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा 'किया जाता है', तो यह आवश्यक है कि वे कृत्य को वास्तव में 'करने' में शामिल हों, न कि केवल उसकी योजना बनाने में।"

79. उसी मामले में, इस बिंदु पर प्रिवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों द्वारा एआईआर 1925 पीसी 1 (सी) मामले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को सहमति के साथ उद्धृत किया गया था:

> "अपराध को वास्तव में अंजाम देने में 'भागीदारी और संयुक्त कार्रवाई' सार रूप में ऐसे मामले हैं जो उकसाने या प्रयास करने के विपरीत हैं।"

80. इस संबंध में आईपीसी की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर को लॉर्ड समनर ने प्रसिद्ध मामले एआईआर 1925 पीसी 1 (सी) में इस प्रकार स्पष्ट किया है:

> "उद्देश्य और इरादे में अंतर है, क्योंकि यद्यपि उनका उद्देश्य एक ही है, विभिन्न सदस्यों के इरादे भिन्न हो सकते हैं और वास्तव में केवल इस मायने में समान हो सकते हैं कि वे सभी गैरकानूनी हैं, जबकि धारा 34 की प्रमुख विशेषता, यानी अपराध में सहभागिता का तत्व, धारा 149 में अपराध करते समय सभा की सदस्यता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।"

81. बशीर बनाम राज्य, एआईआर 1953 ऑल 668 (एफ) मामले में, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ का निर्णय है, न्यायमूर्ति देसाई ने टिप्पणी की थी कि:–

> "धारा 34 के तहत जिन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाना है, उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया होना चाहिए जो 'आपराधिक कृत्य' में शामिल हो। जो व्यक्ति आपराधिक कृत्य करने में शामिल नहीं है, उसे इस धारा के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता", (पृष्ठ 671, स्तंभ 1)।

82. फैयाज खान बनाम रेक्स, एआईआर 1949 ऑल 180 (जी) मामले में यह माना गया था कि:–

> “धारा 34 उन मामलों से संबंधित है जिनमें कई व्यक्ति किसी कार्य को करने का इरादा रखते हैं और उसे करते हैं। यह उन मामलों से संबंधित नहीं है जहां कई व्यक्ति किसी कार्य को करने का इरादा रखते हैं और उनमें से एक या अधिक व्यक्ति पूरी तरह से अलग कार्य करते हैं। बाद वाले प्रकार के मामलों में धारा 149 लागू हो सकती है, लेकिन धारा 34 लागू नहीं होती”, (पृष्ठ 184, स्तंभ 1)।

83. कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के मामले, एआईआर 1924 कलकत्ता 257 (डी) में, न्यायमूर्ति कमिंग ने टिप्पणी की कि:

> “अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य अभिव्यक्ति में कई व्यक्तियों का एक साथ मिलकर किसी सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करना और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अंतिम परिणाम की पूर्ति के लिए कोई कार्य करना शामिल है, जो विभिन्न कृत्यों से मिलकर अंतिम कृत्य बनता है”, (पृष्ठ 312, स्तंभ 2)।

84. आयद्रूस बनाम सम्राट, एआईआर 1923 मद्रास 187 (2) (एच) में यह माना गया कि धारा 34 के आवेदन को उचित ठहराने के लिए, आरोपी द्वारा किए गए किसी विशिष्ट कृत्य का साक्ष्य आवश्यक है, जिसे विचाराधीन आपराधिक कृत्य का हिस्सा माना जा सकता है। (देखें एच.एन. (बी))।

85. कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पीठ के निर्णय, अब्दुल कादर बनाम सम्राट, एआईआर 1946 कलकत्ता 452 (आई) में न्यायमूर्ति शार्प की निम्नलिखित टिप्पणियाँ भी इसी आशय की हैं:

> “हम फाजू खान बनाम जटू खान, एआईआर 1931 कलकत्ता 643 (जे) के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करना उचित समझते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ‘सभी आरोपियों को दंड संहिता की धारा 34 के तहत किसी अपराध का दोषी तभी ठहराया जा सकता है जब यह पाया जाए कि उनमें से प्रत्येक ने अपराध करने में या उसके प्रति किसी न किसी रूप में भाग लिया हो’।”

86. यह सत्य है कि किसी विशेष अभियुक्त को धारा 34 के तहत किसी अपराध, जैसे हत्या, के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसने वास्तव में घातक प्रहार किया हो, बल्कि उसके किसी कार्य या आचरण का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए जिससे यह प्रदर्शित हो कि वह हत्या करने के सामान्य इरादे में भागीदार था" (पृष्ठ 457-458)।

87. उपरोक्त चर्चा का सार यह है कि यद्यपि धारा 34 एक संयुक्त आपराधिक कृत्य और एक सामान्य इरादे से संबंधित है, यह नहीं कहा जा सकता कि यह इन दोनों मामलों में व्यक्तिगत अपराधी के व्यक्तिगत योगदान के तत्व को पूरी तरह से अनदेखा या समाप्त कर देती है।

88. दूसरी ओर, आईपीसी की धारा 34 की एक पूर्व शर्त यह है कि व्यक्तिगत अपराधी ने इन दोनों मामलों में अपराध में भाग लिया हो। उसने कुछ ऐसा किया हो, चाहे वह कितना भी मामूली हो, या किसी तरह से आचरण किया हो, चाहे वह कार्य करके हो या कार्य न करके, जिससे यह संकेत मिले कि वह अपराध में भागीदार और उसमें दोषी सहयोगी था। उसे यह भी होना चाहिए कि वह व्यक्तिगत रूप से वह किसी ऐसे इरादे का पक्षकार होता है जिसे उसे दूसरों के साथ साझा करना होता है।

89. दूसरे शब्दों में, उसे 'आपराधिक कृत्य' और 'सामान्य इरादे' दोनों में भागीदार होना चाहिए, जो आईपीसी की धारा 34 के दोहरे पहलू हैं। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, आरोपी के लिए न्यायालय के समक्ष यह तर्क देना कठिन है कि आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 34 का उल्लेख होने के कारण, उसे गुमराह किया गया या उसके बचाव में पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसे यह मान लेना पड़ा कि इसके परिणामस्वरूप उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस विषय पर कानून जानता हो और यदि इसके बावजूद वह इस तरह के किसी भ्रम में पड़ जाता है, तो वह ऐसा अपने जोखिम पर करेगा। [देखें: ओम प्रकाश (उपरोक्त)]

90. जैसा कि इस न्यायालय ने सुरेश सखाराम नांगरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2012 (9) जजमेंट्स टुडे 116 में कहा है, यदि सामान्य इरादा सिद्ध हो जाता है, लेकिन किसी प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप किसी आरोपी पर नहीं लगाया जाता है, तो संहिता की धारा 34 लागू होगी क्योंकि इसमें मूलतः परोक्ष दायित्व शामिल है। लेकिन यदि अपराध में आरोपी की सहभागिता सिद्ध हो जाती है और सामान्य इरादा अनुपस्थित है, तो धारा 34 लागू नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, इसके लिए एक पूर्व-नियोजित योजना की आवश्यकता होती है और पूर्व-सहमति की परिकल्पना की जाती है, इसलिए विचारों का मेल होना आवश्यक है।

91. राज्य की ओर से पेश हुए श्री सिंहवी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का भी हवाला दिया। हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में यह धारा लागू नहीं होती। यह सच है कि जब अपराध घर की चारदीवारी के अंदर और गुप्त रूप से हुआ हो, तो घर में रहने वाले परिवार के सदस्य ही सबसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। फिलहाल हम यह मानकर चलते हैं कि घटना के समय पति वहां मौजूद था, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उसका अपनी मां के साथ कोई साझा इरादा था। जब सास ने मृतक पर केरोसिन डालकर आग लगा दी, तो संभव है कि पति डर के मारे अपनी पत्नी के जलते हुए शरीर पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने के बाद घर से भाग गया हो। धारा 106 के तहत पति को भी कथित अपराध में फंसाने के लिए, अभियोजन पक्ष को प्रथम दृष्टया ऐसे आधारभूत तथ्य प्रस्तुत करने होंगे जो कथित अपराध में उसकी संलिप्तता या भागीदारी को दर्शाते हों। घटना के बाद उसका अचानक गायब हो जाना सामान्य इरादे का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

92. मामले के समग्र अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय ने सास को कथित अपराध का दोषी ठहराया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पति-अपीलकर्ता संख्या 1 को आईपीसी की धारा 34 की सहायता से हत्या का दोषी ठहराने में त्रुटि की है।

93. परिणामस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से सफल होती है। अपीलकर्ता संख्या 2 के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि आदेश की पुष्टि की जाती

है। अपीलकर्ता संख्या 1 के संबंध में, अपील सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता संख्या 1 को सभी आरोपों से बरी किया जाता है।

94. हमें सूचित किया गया है कि सास पहले से ही जेल में है।

95. हमें यह भी सूचित किया गया है कि पति-अपीलकर्ता संख्या 1 भी जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए।

96. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

97. लंबित आवेदन (यदि कोई हो) निपटा दिए गए हैं।

मामले का परिणाम: अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद सुधीर, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।